Goverment should give certain *powers* to the zila Parliments as it has been done in Statas. in States, the Para are appokting the seldom, constructing the aatthtp and as .They will be the people. I agee that dacantraliation is going to help in the development al primary schools. In pria-ciple, I agree with the HON. Member as this point. We have no objection if the State Government decides it.

मुजफ्फरनगर और मेरठ में रेलवे पुलों का निर्माण

*423. श्रीमती मालती शर्मा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कुल कितने रेलवे पुलों का निर्माण किया गया और उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1996 में कितने रेलवे पुलों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ग) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर और मेरठ में रेलवे पुलों के निर्माण हेतु कोई आवेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त रेल पुलों का निर्माण-कार्य कब तक आरम्भ कर दिया जायेगा?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है:—

आंध्र प्रदेश	—	6
बिहार	—	3
दिल्ली	—	6
गुजरात	—	2
हरियाणा	—	5
जम्मू-कश्मीर	—	1
कर्नाटक	—	1
केरल	—	2
मध्य प्रदेश	—	5
महाराष्ट्र	—	4
उड़ीसा	—	5
पंजाब	—	3
राजस्थान	—	1
तमिलनाडु	—	2
उत्तर प्रदेश	—	5
पश्चिम बंगाल	—	1
जोड़:		52

(ख) अनुपलब्ध।

(ग) से (ङ) समपार फाटकों के बदले ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण के बारे में रेलें समपार में भिन्नता के आधार पर विचार करती हैं और इसके लिए राज्य सरकार को अपने हिस्से की लागत वहन करने की सहमति देते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत करने होते हैं। मुजफ्फरनगर और मेरठ के लिए इस तरह का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। बहरहाल, मेरठ जिले में दो ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण का कार्य स्वीकृत है, जिनमें से एक किलोमीटर 59/6-7 पर समपार संख्या 21-ए के बदले परतापुर में और दूसरा किलोमीटर 91/8-9 पर समपार सं॰ 40-बी के बदले सकौती-टांडा में है।

श्रीमती मालती शर्मा: मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि मेरठ और मुजफ्फरनगर में बहुत बड़ी समस्या वाले दो पुल आपने स्वीकृत कर दिए हैं। किन्तु माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में 'ग' भाग का उत्तर नहीं दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि ये पुल कब तक बनना प्रारंभ हो जायेंगे और कब तक उनको बनाकर समाप्त कर दिया जाएगा?

श्री राम विलास पासवान: सभापति जी, किसी भी पुल को जब हम स्वीकृति देते हैं तो उसकी जवाबदेही पहले राज्य सरकार पर जाती है। राज्य सरकार का काम होता है कि जमीन का वह एक्विजिशन करे और उसके बाद हम फंड देते हैं, फंड देने का हम काम करते हैं परतापुर में और सकौती टांडा में—सकौती टांडा जो प्रोजेक्ट है वह 1987-88 में सेक्शन किया गया था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं मुजफ्फरनगर और मेरठ के इलाके कितने महंगे पड़ते हैं। इसलिए जिनकी जमीन है वे जमीन देते नहीं है और कभी-कभी रिप्रजन्टेटिव्स आ जाते हैं इसको इधर से उधर कीजिए। इसको इन्कलूड किया गया था 1987-88 में। लेकिन जमीन नहीं मिलने के कारण फिर उसको ड्रोप कर दिया गया। फिर आप लोगों ने जब प्रेसर डाला और कहा तो उसको फिर शामिल किया गया है। राज्य सरकार से जो रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक जमीन का अधिग्रहण किया जा

रहा है। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है, वह इस संबंध में नहीं है। लेकिन हमको सूचना मिली है कि जमीन अधिग्रहण करने की प्रक्रिया जारी है। उसी तरह से यह कमोली टांडा पर है। फतेहपुर का भी मामला है। इसको 1994-95 में टेकअप नहीं किया गया था। अब सैंक्शन किया गया है। सैंक्शन तो कर दिया है लेकिन अभी तक स्टेट गवर्नमेंट ने इस संबंध में जो कार्यवाई शुरू करनी चाहिए थी जमीन अधिग्रहण वगैरह की, मेरी जानकारी के मुताबिक अभी तक कार्यवाई शुरू नहीं की गई है।

एक चीज उसके लिए आप बहुत इंटरेस्टेड रहती हैं वह है मुजफ्फरनगर में—फुट ओवर ब्रिज जिसका मैंने यहां जिक्र नहीं किया था। लेकिन चूंकि आप उस मामले में हमेशा दिलचस्पी रखी है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं यह बताता हूं कि वर्ष 1997-98 के प्रोजेक्ट में इसको शामिल कर लिया गया है।

श्रीमती मालती शर्मा: मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने पुल की जो बात कही है, बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं केवल इतनी जानकारी चाहती हूं कि दो वर्ष पहले मोदी नगर से मेरठ तक के लिए डबल लाईन का प्रस्ताव सरकार ने पास किया था। वह डबल लाईन आज तक आरम्भ नहीं हुई। मैं आपसे यह जानकारी चाहती हूं कि केवल यह कागजों पर ही पुल बनेंगे या फिर हम जनता को जाकर क्या बताएं कि यह पुल बनने कब तक प्रारम्भ हो जाएंगे। यह सरकार और आपके बीच की जो कार्यवाई है उसको जनता नहीं जानती, आप जानते हैं। मैं तो केवल आपसे यह आश्वासन चाहती हूं कि कब तक आप इस पुल के निर्माण का कार्य प्रारम्भ करा देंगे? अन्यथा तो वहां कुछ दुकानें बनी हुई हैं। वह दुकानदार लोग अदालत से स्टे ले लेते हैं कभी आप जमीन के अधिग्रहण की बात कर देंगे। तो फिर मामला खटाई में पड़ जाएगा। इसलिए मैं मंत्री जी से जानकारी चाहती हूं। उत्तर प्रदेश में आप ही की सरकार है। आप मुझे आश्वासन देंगे कि यह पुल कब तक बनना प्रारम्भ हो जाएगा?

श्री राम विलास पासवान: माननीय सदस्या किस पुल के संबंध में पूछ रही हैं। क्या आप डबल लाईन के संबंध में पूछ रही हैं?

श्रीमती मालती शर्मा: पुल संख्या-40, कमोली टांडा। फुट ओवर ब्रिज मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन। दोनों के विषय में।

श्री राम विलास पासवान: मैंने तीनों की स्थिति आपको बताई कि अपनी तरफ से राज्य सरकार को लिखेंगे। राज्य सरकार मेरी नहीं है लेकिन मैं अपनी तरफ से राज्य सरकार को लिखूंगा। हमारा जो रेलवे का पैसा है, शेयर है हम तैयार रखे हुए हैं। जब राज्य सरकार काम शुरु कर देगी हम अपना पैसा उसमें डाल देंगे।

श्रीमती मालती शर्मा: माननीय मंत्री जी, मैं केवल आपसे इतना निवेदन करना चाहती हूं कि जल्दी से आप अपनी सरकार को लिखिए कि वह वहां जमीन का अधिग्रहण जल्दी करे। इसका आश्वासन आप हमें दें कि आप कब तक कार्यवाई करेंगे?

श्री राम विलास पासवान: हमारी सरकार हो या किसी की सरकार हो जो सरकार होगी उसको हम लिख देंगे।

श्रीमती मालती शर्मा: मेरा सेकेंड क्वेश्चन है—सप्लीमेंट्री।

MR. CHAIRMAN: You put your second question.

श्रीमती मालती शर्मा: माननीय मंत्री जी ने 5 पुलों के बनाने की बात कही है उत्तर प्रदेश में। वह 5 स्थान कौन-कौन से है?

श्री राम विलास पासवान: सभापति महोदय, मुजफ्फरनगर और मेरठ में जो अभी तक पुल निर्माण हो रहे हैं वह गाजियाबाद, सहारनपुर, मेरठ में है। दूसरा मुजफ्फरनगर में, तीसरा मुजफ्फरनगर में है। जो हैं उनका मैंने विवरण दे दिया है। जो आवश्यकता है उनका मैंने पता भी लगाया कि कहां-कहां बनाने की आवश्यकता है। उसमें मेरठ कैंट का मामला है, उसमें दौराला है, खतौली में है, मुजफ्फरनगर में है, शामली में है। यह जो पांच जगह है वहां पुल बनाने की आवश्यकता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जो आवश्यकता है उसकी रिकमंडेशन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आती है। जब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आता है तो रेलवे उसके ऊपर विचार करता है। तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक इसके संबंध में रिक्वेस्ट नहीं आया है।

श्री नरेन्द्र नाथ ओझा: सभापति महोदय, रेलवे के ऐसे भी पुल हैं जो इतनी जर्जर हालत में हैं कि उनका इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है और ट्रेक पर चलने वाली पैसेंजर ट्रेन के जाने के बाद चलती है। ऐसे कितने पुल हैं जो इस हालत में हैं और मैं इसी के साथ उदाहरण देना चाहूंगा कि समस्तीपुर मंडल के अंदर पूर्वी रेलवे की कुमरांय में एक ऐसा ही पुल है।

जो बन नहीं रहा है और वहां एक-दो ऐसे इंसीडेंट भी हुए कि रेल से कटकर लोग मरे। मेरा मंत्री महोदय से प्रश्न है कि प्लेटफार्म से उतरकर इस पार या उस पार जाने के लिए जो अभी जर्ज हालत में ब्रिज है उसकी मरम्मत के लिए या उसको बनाने के लिए क्या उपाय करने जा रहे हैं?

श्री राम विलास पासवान: महोदय, जहां तक रेलवे के पुल का सवाल है उसमें तो हमेशा हम इन्क्वायरी करवाते रहते हैं। कहीं कोई भी पुल अभी तक ऐसा नहीं आया है जो रेलवे का हो और टूटा हो या इस तरह का हो। माननीय सदस्य ने जिस पुल को, डुमरांव के पुल का कहा है, उस पुल की जांच करवाएंगे उसमें रेलवे का कितना मामला है या कितना पुल का पुराना होने का मामला है या स्टेट गवर्नमेंट का है। हम उसकी जांच करवाएंगे।

एक माननीय सदस्य: बिल्कुल रेलवे का है।

श्री ईश दत्त यादव: सभापति जी, श्रीमती मालती शर्मा जी का जो प्रश्न है, इसी आशय का प्रश्न पिछले सत्र में भी इनका था। उस समय भी मुझे पूरक प्रश्न पूछने का अवसर मिला था। आज भी आप की महती कृपा है। उस समय जो मैंने प्रश्न पूछा था, वही फिर माननीय रेल मंत्री जी से पूछने जा रहा हूं। उस समय उत्तर प्रदेश में श्री मुलायम सिंह जी मुख्य मंत्री थे। उनके प्रयास से इटावा में रेलवे अंडर ब्रिज बनाने के लिए रेल मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा गया था। श्री जनेश्वर मिश्र जी, तत्कालीन रेल मंत्री ने इसकी स्वीकृति दे दी। लेकिन दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश की सरकार बदल गयी। तो दुर्भावना से उस समय की सरकार ने इस अंडर ब्रिज का बनना रोक दिया। फिर जब मैंने श्री जाफर शरीफ साहब को, रेल मंत्री जी को इसके संबंध में पत्र लिखा और श्रीमती मालती शर्मा जी के प्रश्न पर पूरक प्रश्न पूछा तो तत्कालीन रेल मंत्री जाफर शरीफ साहब ने आश्वासन दिया कि जून सन् 1996 तक इटावा का रेलवे अंडर ब्रिज पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन मान्यवर, काम शुरू नहीं हो सका। श्री राम गोपाल यादव जी, जो हमारे माननीय सदस्य हैं इस सदन के इन्होंने एक पत्र...

MR. CHAIRMAN: Please put the question. Don't tell the whole story.

श्री ईश दत्त यादव: नहीं सर, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। माननीय राम विलास पासवान जी को लिखा और इन्होंने आश्वासन दिया—मैं इनकी प्रशंसा करूंगा—कि इस पुल पर शीघ्र कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। इनके आदेश से कार्य तो प्रारंभ कर दिया गया है लेकिन गति बहुत धीमी है और माननीय रेल मंत्री, पासवान जी ने आश्वासन दिया है कि अब जून 1997 तक इसको पूरा कर दिया जाएगा। परन्तु मुझे आशंका है कि जिस धीमी गति से यह काम हो रहा है, वह काम पूरा नहीं होगा। मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि आपने जो समय निश्चित किया है, समय दिया है उसके अंदर क्या पूरा कराने की कोशिश करेंगे?

श्री राम विलास पासवान: हम पूरा कराने की कोशिश ही नहीं करेंगे, हम पूरा करवाएंगे यदि मुझे रहने का मौका मिला तो ....(व्यवधान) सरकार सरकार है ...(व्यवधान)

जहां तक पुल का सवाल है, पुल सैक्शन्ड है, काम प्रोग्रेस पर है। मुलायम सिंह यादव जी ने भी हमसे कहा था, राम गोपाल जी ने भी हमसे कहा था। मैंने अपने अधिकारियों को निर्देश भी दिया है इसी पुल के संबंध में ही नहीं बल्कि मेरी मान्यता है कि जो काम टेक अप किया है वह जल्द से जल्द हो और उसको पूरा कर लिया जाए। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि यदि उस काम में ढिलाई होगी तो वह ढिलाई नहीं करने दी जाएगी और आवश्यकता पड़ेगी तो कभी उस रास्ते से चलेंगे तो हम इटावा भी पहुंच जाएंगे।

श्री सूर्यभान पाटिल वाझ्हदने: माननीय सभापति जी, रेलवे क्रासिंग्स पर चार पुल महाराष्ट्र में होने जा रहे है। उनके नाम क्या है और राज्य की ओर से जो राशि आनी चाहिए केन्द्र की ओर, वह आई है या नहीं और वह राशि कितनी है?

श्री राम विलास पासवान: उसका पूरा विवरण आपको भेज दूंगा।

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: 1 would like to know from the hon. Minister the number of bridges pending in Andhra Pradesh. How many have been sanctioned in 1996-97? What is the Budget allocation for these projects? For the last 10 years we have been requesting for sanction of two flyovers --------- one, Sitafal Mandi and one, Jamia Osmania bridge—but nothing, has happened so far. Ten years back I had made a representation and h is being negotiated since then. Would the Minister reply to these questions?

श्री राम विलास पासवान: सर, आन्ध्र प्रदेश में जो निर्माणाधीन पुल हैं वे 1996-97 के मुताबिक 17 हैं और बाकी जो चीज़ आपने डिटेल में मांगी है उसको भी हम लिख कर भेज देंगे।

Potential Landing Sites for Fish in Andhra Pradesh

*424. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whetner Government have taken any steps to update the techno-feasibility studies done on potential landing sites for fish on the coast of Andhra Pradesh;

(b) if so. when was the study done;

(c) the names of potential fish landing centres thus studied in Andhra Pradesh; and

(d) the economic potential of each such site?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) to (d) A statement is laid on the Tablc of the Sabha.

Statement

(a) to (d) The Central Institute of Coastal Engineering for Fisheries, Bangalore, after collecting techno economic data during May, 19% in collaboration with the State Government have now taken up the job of preparing the techno-economic feasibility report for the development of fishing harbour at Krishnapatnam in Nellore district of Andhra Pradesh.

The Government of Andhra Pradesh have also conducted techno-feasibility studies during 1994 and shortlisted four sites for setting up fish landing centres, namely (1) Pedamainavanilanka in West Godvari district, (2) Chinnagollapalem in Krishna district, (3) Gondisamudram (Nakshatrapuram) in Guntur district (4) Gundayapalem in Prakasam district.

The estimated fish landings, their value and number of fishing villages covered by each site arc as follows:

Possible sites identified for Fishing Harbours/Fish Landing Centres	Estimated catch (m. tonnes)	Estimated value (Rs.)	Estimated beneficiaries (nos)	
			Villages	Fishermen
1. Kirishnapatnam	18,200	18,00,00,000	6	3224
2. Pedamainavanilanka	958	1,72,44,000	1	690
3. Chinnagollapalem	15,300	27,54,00,000	5	6000
4. Gondisamudram (Nakshatrapuram)	503	90,54,00,000	8	1403
5. Gundayapalem	900	1,62,00,000	1	500

SHRI V. HANUMANTHA RAO: Mr. Chairman, Sir, Andhra Pradesh has a long coastal line and there is a great potenfial for developing the fishing industry there. I would like to know what steps the Government is taking to develop landing centres in Andhra Pradesh in the 9th Five Year Plan. It is felt that there is potential for developing fishing centres near Narsapuram in West Godavari district and in Nizamapaftum near Guntur. But they have been ignored by the Fishery Development Authority of the Ministry. How dees the Govenment propose to assist the Andhra Pradesh Government in developing such landing centres?